Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 18-03-2006

Participants : Chavda Shri Harisinh

an>

Title : Need to ensure payment of Minimum Support Price for Raida Crop to the farmers in the Country.

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में रायड़ा यानी मस्टर्ड का उत्पादन बहुत हुआ है, जिससे किसान बहुत खुश हैं। किसानों को फायदा हो, इसलिए सरकार ने सरसों की सपोर्ट प्राइस तय की है। लास्ट टाइम यह 340 रुपए प्रति क्विंटल, 1700 क्विंटल तक और इस टाइम 343 रुपए प्रति क्विंटल, 1715 क्विं वटल तक निर्धारित की है, जो अच्छी बात है।

महोदय, न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा लास्ट टाइम भी किसानों को नहीं मिला क्योंकि बीच में नैफैड, गुजरात को-आपरेटिव डिपार्टमेंट, गुटको और माथोट संस्थाओं के कर्मचारियों और सहकारी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने मिलीभगत कर के किसानों से सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी। किसानों को अपनी सरसों मजबूरी में बहुत सस्ते में लोकल व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन लोगों ने स्थानीय व्यापारियों से सस्ते में सरसों खरीद ली और उसे सरकार को समर्थन मूल्य पर बेच दिया। इस प्रकार उन्होंने हजारों और लाखों रुपए का भ्रटाचार किया। किसान से लोकल व्यापारी 260 और 270 रुपए प्रति क्विंटल में सरसों खरीद लेते थे और वही सरसों नैफेड, को-आपरेटिव और गुजरात की संस्थाओं के कर्मचारियों और सहकारी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार को 343 रुपए प्रति क्विंटल पर बेच दी जाती थी। सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 343 रुपए प्रति क्विंटल इसलिए तय किया ताकि किसानों को फायदा हो, लेकिन किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस भ्रटाचार को खत्म करने के लिए यदि जरूरत हो, तो नैफैड, गुजरात को-आपरेटिव डिपार्टमेंट, गुटको और माथोट संस्थाओं को सरसों की खरीद के काम में न लगाकर किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से सरसों की खरीद किसानों से कराई जाए जिससे किसानों को सीधा फायदा मिल सके क्योंकि हमारी सरकार किसानों का फायदा करना चाहती है औरों का नहीं। यही मेरी रिक्वैस्ट है।